EDU TERIA
E - D.N.A
Daily Newspaper Analysis
Prelims Mains Essay
By- Nikhil Ranjan

Useful For Prelims

Date: 07 January 2026

पहली हाइड्रोजन ट्रेन फर्राटा भरने को तैयार

बदलाव

चंडीगढ़, एजेंसी। हरियाणा में देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन से लैस ट्रेन दौड़ने को तैयार है। राज्य सरकार ने मंगलवार को बयान जारी कर ये जानकारी दी। बयान के अनुसार उत्तरी रेलवे की महत्वाकांक्षी परियोजना अंतिम चरण में है। ये ट्रेन जिंद और सोनीपत के बीच चलेगी जो कुल 89 किलोमीटर का रूट होगा।

हाइड्रोजन ट्रेन को सुचारू ढंग से ऊर्जा मुहैया कराने के लिए 11 किलोवाट का हाइड्रोजन प्लांट जींद में स्थापित किया गया है। इसी से ट्रेन को निर्बाध ऊर्जा उपलब्ध कराई जाएगी। उसकी ऊर्जा भंडारण क्षमता तीन हजार किलोग्राम है। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने परियोजना को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और जरूरी दिशा- निर्देश दिए।

89 किलोमीटर का रूट है, जिस पर दौड़ेगी ट्रेन

11 केवी का हाइड्रोजन संयंत्र तैयार

03 हजार किग्रा संयंत्र की भंडारण क्षमता

सुविधा-सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

1. ट्रेन की अधिकतम गति 150 किमी प्रतिघंटा
2. लीक की स्थिति से निपटने को सेंसर लगे
3. तापमान नियंत्रण और वेंटिलेशन का इंतजाम
4. जर्मन कंपनी टीयूवी सुरक्षा जांच करेगी
5. ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन शून्य करने में मदद

आठ कोच से सफर होगा सुगम

योजना के अनुसार पहले चरण में ट्रेन को दस कोच के साथ चलाया जाएगा। इसमें एक साथ कुल दो हजार यात्री सफर कर सकेंगे।

हाइड्रोजन ट्रेन चलाने के लिए दो डीजल इंजन को रेट्रोफिट के लिए भेजा गया है। इस प्रक्रिया के तहत दोनों इंजन में हाइड्रोजन फ्यूल प्रणाली लगेगी। सिलेंडर में 220 किलोग्राम गैस भरी जा सकेगी।

गडकरी ने हाइड्रोजन कार की सवारी की

नई दिल्ली। केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ मंगलवार को टोयोटा मिराई ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन की एकसाथ सवारी की। ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन को बढ़ावा देने की दिशा में ये बड़ी उपलब्धि है। केंद्रीय मंत्री जोशी ने भारत मंडपम से केंद्रीय मंत्री गडकरी के आवास तक मिराई चलाई। मालूम हो कि टोयोटा 'मिराई' दूसरी पीढ़ी का हाइड्रोजन ईंधन-सेल इलेक्ट्रिक वाहन है।

Hindustan Page

> गरीबी उन्मूलन केवल आर्थिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय का संकल्प है। जब विकास की रोशनी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती है, तभी लोकतंत्र और राष्ट्र दोनों मजबूत होते हैं।
>
> **अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री**

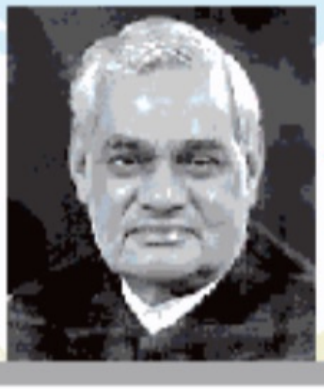

क्या आप जानते हैं

दुर्लभ खनिज संपदा से भरा हुआ है ग्रीनलैंड

56

हजार की आबादी वाला यह बड़ा-सा द्वीप अमेरिका के लिए इसलिए अहम बन गया है, क्योंकि...

- यहां यूरेनियम, लोहा और दुनिया के सबसे दुर्लभ खनिज बड़ी मात्रा में हैं
- बर्फ पिघल रही है, जिससे दबे हुए खनिजों को निकालना आसान है
- अमेरिकी राष्ट्रपति इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बहुत अहम मानते हैं
- यह क्षेत्र भविष्य में व्यापार और सुरक्षा के नजरिए से भी महत्वपूर्ण है
- यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, जो किसी महाद्वीप का हिस्सा नहीं है
- इसकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से मछली पकड़ने पर निर्भर है

Hindustan Page-20

औद्योगिक विकास के लिए बजट में बड़े कदम उठाने होंगे

योजनाओं के लिए पर्याप्त बजटीय समर्थन की दरकार : बीआईए

पटना, वरीय संवाददाता। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (बीआईए) का मानना है कि बिहार आज अपने आर्थिक विकास की यात्रा के एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। देश का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य होने के बावजूद बिहार प्रति व्यक्ति आय, विद्युत खपत और शहरीकरण जैसे प्रमुख विकास संकेतकों पर राष्ट्रीय औसत से काफी पीछे है।

वर्ष 2047 तक भारत को 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बिहार को भी राष्ट्रीय विकास गति के साथ आगे बढ़ना होगा। इसके लिए राज्य सरकार के बजट 2026-27 में उद्योग-केंद्रित नीतियों और निवेश को प्राथमिकता देना आवश्यक है।

मंगलवार को राज्य सरकार की ओर से आयोजित बजट-पूर्व संवाद में बीआईए द्वारा उद्योग विभाग के बजट को वर्तमान 0.5 प्रतिशत से बढ़ाकर

05 प्रतिशत करने की मांग की उद्योग विभाग के बजट को बढ़ाकर

- राज्य सरकार के बजट पूर्व संवाद में बीआईए ने रखी अपनी राय

कम से कम 5 प्रतिशत करने की मांग की है। एसोसिएशन ने बिहार को पूर्वी भारत के नए टेक हब के रूप में विकसित करने, डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर पार्क, मेगा टेक सिटी, फिनटेक सिटी, मेगा फूड पार्क और एमएसएमई पार्क जैसी योजनाओं के लिए पर्याप्त बजटीय समर्थन की आवश्यकता पर जोर दिया।

बीआईए ने राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस वे के समीप औद्योगिक टाउनशिप विकसित करने, रुग्ण उद्योगों के पुनर्वास, कार्यरत इकाइयों के उत्पादन विस्तार, निजी औद्योगिक पार्कों को बढ़ावा देने और राज्य में 500 एकड़ का फार्मा पार्क स्थापित करने का सुझाव दिया है। संगठन ने निर्यात-आयात को बढ़ावा देने के लिए लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एयर कार्गो और इनलैंड कंटेनर डिपो के विकास की मांग की। बीआईए ने पटना में स्थायी औद्योगिक प्रदर्शनी स्थल, उद्योगों के लिए भूमि का पृथक वर्गीकरण तथा पटना पर जनसंख्या का दबाव कम करने के लिए आरआरटीसी परियोजना पर कार्य शुरू करने का भी सुझाव दिया है। बीआईए का मानना है कि इन सुझावों को बजट 2026-27 में शामिल किए जाने से बिहार में निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी, जिससे राज्य और देश दोनों के विकास को मजबूती मिलेगा।

Dainik Jagaran Page

Jansatta Page No-14

आर्थिक सुधार और व्यापार समझौते देंगे नई दिशा | आर्थिकी | भारतीय रुपया औसतन 92.26 प्रति डालर रहेगा

भारत की वृद्धि दर 6.9 फीसद रहने का अनुमान

नई दिल्ली, 6 जनवरी (भाषा)।

साख निर्धारित करने वाली इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने आगामी वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.9 फीसद रहने का अनुमान लगाया है।

रेटिंग एजंसी का कहना है कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) तथा आयकर में कटौती जैसे प्रमुख सुधार और व्यापार समझौते, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के रूप में काम करेंगे। साथ ही अर्थव्यवस्था को वैश्विक उथल-पुथल से बचाएंगे। इंडिया रेटिंग्स के मुख्य अर्थशास्त्री देवेंद्र कुमार पंत ने कहा कि अर्थव्यवस्था में अगले वित्त वर्ष में भी उच्च वृद्धि दर और कम महंगाई दर (औसतन 3.8 फीसद खुदरा महंगाई) की स्थिति बनी रहेगी।

रेटिंग एजंसी का कहना है कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) तथा आयकर में कटौती जैसे प्रमुख सुधार और व्यापार समझौते, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के रूप में काम करेंगे। साथ ही अर्थव्यवस्था को वैश्विक उथल-पुथल से बचाएंगे। इंडिया रेटिंग्स के मुख्य अर्थशास्त्री देवेंद्र कुमार पंत ने कहा कि अर्थव्यवस्था में अगले वित्त वर्ष में भी उच्च वृद्धि दर और कम महंगाई दर (औसतन 3.8 फीसद खुदरा महंगाई) की स्थिति बनी रहेगी। कम शुल्क वाले भारत-अमेरिका व्यापार समझौते से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि के आंकड़ों में और इजाफा होगा। एजंसी ने चालू वित्त वर्ष में आधार वर्ष 2011-12 पर आधारित जीडीपी वृद्धि 7.4 फीसद और बाजार मूल्य पर जीडीपी नौ फीसद रहने का अनुमान लगाया है। इंडिया रेटिंग्स को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2026-27 में भारतीय रुपया औसतन 92.26 प्रति डालर रहेगा जो मौजूदा वित्त वर्ष में 88.64 प्रति डालर से अधिक है।

एजंसी ने साथ ही कहा कि सरकार के विशेष रूप से न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और ओमान के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) विदेशी निवेश को बढ़ावा देंगे और अधिक विदेशी निवेश को आकर्षित करके चालू खाता घाटा (सीए) को कम रखने में मदद करेंगे। पंत ने कहा कि सीमा शुल्क को युक्तिसंगत बनाना एवं विकसित भारत-राम-जी अधिनियम के तहत आवंटन एक फरवरी को निर्धारित 2026-27 के केंद्रीय बजट में अपेक्षित प्रमुख घोषणाएं होंगी।

इसके अलावा, 16वें वित्त आयोग की रपट को भी एक फरवरी को सार्वजनिक किया जाएगा। इसमें एक अप्रैल से शुरू होने वाले पांच वर्षों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच कर हस्तांतरण के अनुपात का सुझाव दिया गया है। रेटिंग एजंसी के अनुमान के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में कर राजस्व में दो लाख करोड़ रुपए की कमी आएगी।

अमेरिका से ट्रेड डील की अनिश्चितता बड़ी चुनौती

विशेषज्ञों ने कहा, बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए इस मुद्दे की अनदेखी करना नहीं होगा आसान

राजीव कुमार • जागरण

नई दिल्ली: अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर अनिश्चितता आगामी बजट के लिए चुनौती साबित होता दिख रहा है। 50 प्रतिशत शुल्क पहले से जारी है और बदले हालात में अमेरिकी राष्ट्रपति और शुल्क लगाने की धमकी दे रहे हैं। ऐसे में जानकारों का कहना है कि बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस मुद्दे की अनदेखी नहीं कर सकती हैं।

अमेरिका को भारत का सालाना 90 अरब डालर का वस्तु निर्यात है और इनमें से अधिकतर निर्यात रोजगारपरक सेक्टर का है। विशेषज्ञ मानते हैं कि आगामी वित्त वर्ष 2026-27 में विकास दर को सात प्रतिशत से ऊपर रखने के लिए बजट में हर हाल में ऐसे प्रविधान करने होंगे, जिससे मैन्यूफैक्चरिंग और रोजगार सृजन की रफ्तार तेज रहे। अमेरिकी शुल्क से गारमेंट, जेम्स व ज्वेलरी, लेदर जैसे आइटम के निर्यात प्रभावित होते दिख रहे हैं और इतने अधिक शुल्क पर एक लंबे समय तक अमेरिका के बाजार में निर्यात को पहले की तरह जारी रखना आसान नहीं होगा। ऐसे में मैन्यूफैक्चरिंग और रोजगार दोनों प्रभावित होंगे जिससे विकास दर पर असर पड़ेगा। जानकारों का कहना है कि आगामी वित्त वर्ष 2026-27 के लिए फरवरी में पेश होने वाले बजट में पूंजीगत खर्च या इन्फ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले सरकारी खर्च का प्रविधान पहले से ज्यादा रहेगा। चालू वित्त वर्ष में इस मद में 11.2 लाख करोड़ से अधिक का प्रविधान रखा गया है। हालांकि चालू वित्त वर्ष के लिए आवंटित राशि आगामी मार्च तक खर्च होने की उम्मीद नहीं दिख रही है। रेलवे अपने हिस्से की आवंटित राशि का 80 प्रतिशत गत दिसंबर अंत तक खर्च कर चुका है, लेकिन अन्य विभागों की खर्च गति कम है।

पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी की गति को जारी रखना होगा : साक्षी गुप्ता

एचडीएफसी बैंक की प्रमुख अर्थशास्त्री साक्षी गुप्ता का मानना है कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौते की अनिश्चितता को देखते हुए आगामी बजट में सरकार को पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी की गति को जारी रखना होगा और मैन्यूफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जैसी अन्य स्कीम लाने की जरूरत होगी। उन्होंने यह भी कहा कि अभी तक अमेरिका में हमारे निर्यात का बुरा हाल नहीं है, लेकिन जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर जैसे सेक्टर जिनके निर्यात प्रभावित होने की आशंका है, उन सेक्टर के निर्यातक अमेरिका की जगह अन्य देशों में अपने निर्यात की संभावना तलाश सकते हैं।

- रोजगार सृजन के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च में वृद्धि जारी रखनी होगी, मैन्यूफैक्चरिंग भी बढ़ाना होगा
- अमेरिका में भारतीय वस्तुओं पर 50% शुल्क से गारमेंट, ज्वेलरी व लेदर उत्पादों का निर्यात प्रभावित

नए बाजार तलाशना आसान नहीं

फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशंस (फियो) के पूर्व चेयरमैन शरद कुमार सराफ कहते हैं कि निर्यातकों को अब अमेरिका के साथ व्यापार समझौते की कोई उम्मीद नहीं है और वे उस हिसाब से ही तैयारी कर रहे हैं। अन्य निर्यातक भी इसी तरह का कदम उठा सकते हैं। वहीं कुछ अन्य निर्यातकों का कहना है कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है और सैकड़ों ऐसे निर्यातक हैं जो सिर्फ अमेरिका में ही निर्यात करते हैं। उन्हें नए बाजार तलाशने और वहां पैर जमाने में समय लगेगा और तब तक उनका कारोबार प्रभावित हो सकता है।

Dainik Jagaran Page -10

चंद देशों के खतरनाक मंसूबे और बिगड़ती विश्व व्यवस्था

अमेरिका की चौधराहट : निशाने पर कई देश

विगत छह दशक में देखें, तो अमेरिका ने पांच बार ही युद्ध की औपचारिक घोषणा की है, जबकि वह दुनिया में दस से ज्यादा देशों में सीधी और बड़ी सैन्य कार्रवाई कर चुका है। छोटे हस्तक्षेपों की सूची बहुत लंबी है और उसका परोक्ष हस्तक्षेप तो शायद दुनिया के तमाम संघर्षों में नजर आ जाता है। वेनेजुएला के बाद उसकी नजर क्यूबा, कोलंबिया, ग्रीनलैंड पर है। अभी कुछ ही दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति अपने शांति प्रयासों के लिए नोबेल सम्मान मांग रहे थे, लेकिन अब एक साथ अनेक देशों को धमकाते हुए अशांति में योगदान देने लगे हैं।

रूस की महत्वाकांक्षा : यूक्रेन पर शिकंजे की कोशिश

रूस की साम्राज्यवादी मानसिकता बीते एक दशक से सामने आती रही है। फरवरी 2014 में रूस और यूक्रेन के बीच खींचतान की शुरुआत हुई थी और फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर सीधे हमला बोल दिया। इस हमले में हजारों लोग मारे जा चुके हैं। यूक्रेन के अनेक इलाकों पर रूस का पहले भी कब्जा था और अब रूस अपने इलाके के विस्तार में लगा है। यूक्रेन को भड़काने में अमेरिका, नाटो और यूरोपीय देशों का बड़ा हाथ रहा है। अमेरिका अब यूक्रेन की ज्यादा मदद नहीं कर रहा है, इससे भी रूस की महत्वाकांक्षा बढ़ती जा रही है।

चीन की आक्रामकता : करीबी देशों पर ललचाई निगाह

चीन की वाम सरकार के साम्राज्यवादी इरादे किसी से छिपे नहीं हैं। तिब्बत पर कब्जे से ताइवान को कब्जाने के इरादे तक, चीन की नीतियां दुनिया के अनेक देशों को चिंता में डाल रही हैं। चीन भारत की ओर भी अपनी सीमा के विस्तार का मंसूबा रखता है और तनाव बढ़ाता रहता है। चीन का आधिकारिक मत है कि ताइवान चीन का अभिन्न अंग है और पुनर्मिलन अपरिहार्य है। बीजिंग ने इस लक्ष्य को पाने के लिए सैन्य बल के प्रयोग से इनकार नहीं किया है। चीन भी अमेरिका की तरह ही वैश्विक कानूनों को नहीं मान रहा है।

दहशत फैलाती कट्टरता : देशों में सांप्रदायिकता का जहर

ईरान तनाव का एक बड़ा कारण बना हुआ है। फलस्तीन से पाकिस्तान तक, सांप्रदायिक कट्टरता लगातार खतरे पैदा कर रही है। ईरान आतंकी संगठन हमास की मदद करता रहा है। अमेरिका के साथ भी उसके रिश्ते तनावपूर्ण हैं। हालांकि, ईरान में हालात बिगड़ रहे हैं, आशंका जताई जा रही है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई अपने शासन के पतन की स्थिति में मॉस्को भाग जाएंगे। अफ्रीका और लातीन अमेरिका के अनेक देशों में तरह-तरह की कट्टरता को बढ़ावा मिल रहा है।

...और तमाशबीन संयुक्त राष्ट्र : सिर्फ नसीहत

दुनिया में जगह-जगह युद्ध के हालात हैं और 80 साल का हो चुका संयुक्त राष्ट्र केवल मौखिक बयानबाजी तक सिमटा जा रहा है। अमेरिका, चीन और रूस जैसे वीटो पावर वाले देश संयुक्त राष्ट्र की बातों पर कान नहीं दे रहे हैं। पिछले सप्ताहांत वेनेजुएला की घटना, रूस-यूक्रेन युद्ध तथा गाजा में जारी मानवीय संकट के सामने संयुक्त राष्ट्र लाचार हो गया है। सवाल उठ रहे हैं कि यदि संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के अपने पहले वादे को पूरा नहीं कर सकता, तो क्या उसका कोई भविष्य है?

दुनिया में युद्ध

द्वितीय विश्व युद्ध से साल 2001 के बीच दुनिया में 153 क्षेत्रों में युद्ध या संघर्ष हुए।

248 दुनिया में कुल हथियारबंद लड़ाइयां

201 लड़ाइयों की शुरुआत अमेरिका ने की

066 देशों ने बीते वर्षों में आतंकी हमले झेले हैं

आज चल रहे बड़े संघर्ष

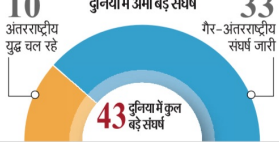

बढ़ती जन हानि

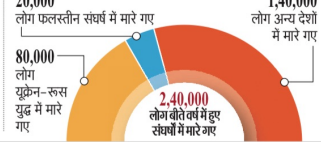

आखिर क्यों हो रहे युद्ध?

दुनिया में युद्ध की सबसे बड़ी वजह प्राकृतिक संसाधन या ऊर्जा है। वेनेजुएला में जो हुआ है, उसके पीछे तेल है। यूक्रेन के खनिज पर रूस ही नहीं, अमेरिका की भी नजर है। दूसरी बड़ी वजह साम्राज्यवादी मानसिकता है। तीसरी वजह, मजहबी द्वेष या सांप्रदायिकता है, जिससे आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है। चौथी बड़ी वजह, गरीबी या आर्थिक विषमता है।

Hindustan Page-15

संकट संकेत सीक्यूडी स्थापित किया गया

1904 में आज ही संकट संकेत सीक्यूडी को मार्कोनी कंपनी द्वारा मानकीकृत समुद्री संकट संकेत के रूप में स्थापित किया गया था, जिसका अर्थ था जल्दी आओ, खतरा है। 1906 में अंतरराष्ट्रीय रेडियोटेलीग्राफिक सम्मेलन में इसे सरल एसओएस से बदल दिया गया था।

Dainik Jagaran Page -14

गैलीलियो ने बृहस्पति के चार चंद्रमाओं की खोज की

1610 में आज ही इतालवी खगोलशास्त्री गैलीलियो गैलीली ने बृहस्पति के चार चंद्रमाओं (आयो, यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो) की खोज की थी। इस खोज ने पृथ्वी-केंद्रित ब्रह्मांड माडल को चुनौती दी और साबित किया कि पृथ्वी के अलावा भी अन्य खगोलीय पिंड किसी और ग्रह की परिक्रमा करते हैं।

श्रद्धांजलि. पूर्व आइओए अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी के निधन पर भारतीय खेल जगत ने जताया शोक

भारतीय खेलों में कलमाड़ी ने लाये थे कई बदलाव

एजेंसियां, नयी दिल्ली

देश के खेल जगत ने मंगलवार को भारतीय ओलिंपिक संघ (आइओए) के पूर्व अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया और इसे भारत में ओलिंपिक आंदोलन के लिए एक बड़ी क्षति बताया. दो दशकों से अधिक समय तक भारतीय खेल प्रशासन में प्रभावशाली हस्ती रहे 81 वर्षीय कलमाडी का मंगलवार तड़के पुणे के एक अस्पताल में निधन हो गया. आइओए की वर्तमान अध्यक्ष पीटी उषा ने एक्स पर लिखा कि आइओए अध्यक्ष के रूप में मैं पूर्व आइओए अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी जी के निधन से बहुत दुखी हूं. वह लगभग दो दशक तक एएफआइ के अध्यक्ष भी रहे, जहां उन्होंने भारत में एथलेटिक्स के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किये. उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं. ओम शांति. भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (एएफआइ) के पूर्व सचिव और कलमाडी के लंबे समय तक सहयोगी रहे ललित भनोट ने इसे व्यक्तिगत क्षति बताते हुए कहा कि भारतीय खेलों खेल के विकास में कांग्रेस के पूर्व सांसद की भूमिका महत्वपूर्ण रही.

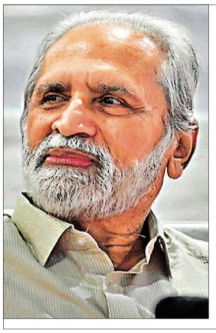

लंबे समय तक खेल संघों से जुड़े रहे

- लगभग दो दशकों तक एएफआइ के अध्यक्ष रहे और उन्होंने खेलों को आगे बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किये.
- एशियाई एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया और विश्व एथलेटिक्स की सर्वोच्च संस्था आइएएएफ की परिषद के सदस्य भी रहे
- भारतीय ओलिंपिक संघ के 1996 से 2011 तक प्रमुख के रूप में एफ्रो-एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया तथा राष्ट्रीय खेलों को पुनर्जीवित किया.
- उनके कार्यकाल में भारत ने 2008 के बीजिंग ओलिंपिक में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की जब निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने देश का पहला व्यक्तिगत ओलिंपिक स्वर्ण पदक जीता
- कलमाड़ी ने पुणे में एथलेटिक्स और खेल अवसंरचना के विकास में भी अहम भूमिका निभायी. उनके प्रयास से ही पुणे अंतरराष्ट्रीय मैराथन शुरू हुई थी, जो भारतीय एथलेटिक्स के कैलेंडर का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गयी.

प्रारंभिक जीवन और करियर

वे भारतीय वायु सेना के पूर्व पायलट थे, जिन्होंने 1965 और 1971 के युद्धों में हिस्सा लिया. एनडीए खड़कवासला से प्रशिक्षण लिया और फर्ग्यूसन कॉलेज,पुणे से शिक्षा प्राप्त की.

राजनीतिक करियर

1982 से राज्यसभा और बाद में लोकसभा (1996, 2004, 2009) से पुणे का प्रतिनिधित्व किया. पीवी नरसिम्हा राव सरकार में रेल राज्य मंत्री रहे.

खेल प्रशासन

1996 से 2012 तक भारतीय ओलिंपिक संघ के अध्यक्ष रहे. 2010 दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों (कॉमनवेल्थ गेम्स) के आयोजन समिति के अध्यक्ष थे. पुणे को खेल शहर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान.

विवाद : 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिसके कारण 2011 में गिरफ्तारी हुई और कांग्रेस से निलंबित कर दिये गये. हालांकि 2025 में प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर उन्हें क्लीन चिट दी थी.

Prabhat khabar Page

Hindustan Page-5

ट्रेन से कानपुर के पनकी होते हुए मुंबई से समुद्र के रास्ते भेजा जाएगा दुबई

बिहटा में ड्राई पोर्ट से पहली बार दुबई भेजा गया कतरनी चावल

बिहटा। बिहटा स्थित प्रिस्टिन मगध ड्राई पोर्ट से सोमवार की शाम पहली बार बिहार का कतरनी और मसूरी चावल दुबई के लिए रवाना किया गया। फूल कस्टम क्लियरेंस चावल को औरंगाबाद स्थित राइस मिल में पैक कराया गया था। बिहटा ड्राई पोर्ट से चावल को ट्रेन से कानपुर के पनकी, फिर नावा सेवा, मुंबई पहुंचाया जाएगा, जहां से समुद्र के रास्ते दुबई भेजा जाएगा।

इस संबंध में प्रिस्टिन मगध ड्राई पोर्ट के क्षेत्रीय प्रबंधक राकेश कुमार ने बताया कि 20 कंटेनरों से चावल भेजे गए। एक कंटेनर में 25 टन चावल हैं। यानी कुल 500 टन चावल रवाना किया गया। श्री कुमार ने कहा यह एक मील का पत्थर है जो प्रिस्टिन बिहटा ड्राई पोर्ट की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं और क्षमताओं को दर्शाता है। बिहार में पहला ड्राई पोर्ट बिहटा में स्थापित किया गया है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। यह सुविधा निर्यात-आयात को बढ़ावा देगी और लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाते हुए स्थानीय किसानों एवं उद्योगों को विकसित करने में मदद करेगी। मौके पर प्रदीप कुमार, आकाश कुमार, संजीव कुमार, रामफूल, सुमित रंजन विवेक विपुल आदि मौजूद थे।

भेजे गए चावल

कुल कंटेनर	20
एक कंटेनर में	25 टन
मसूरी	75 टन
कतरनी	425 टन
कुल चावल	500 टन

बिहटा ड्राई पोर्ट से चावल रवाना होने के दौरान मौजूद अधिकारी व कर्मी।

90 कंटेनर भेजे गए थे रूस: इससे पहले अक्टूबर 2024 में बिहटा ड्राइपोर्ट से इसके पहले 90 कंटेनरों की खेप रूस भेजी जा चुकी है। 90 कंटेनरों में से सात में खाद्य पदार्थ, जूते और स्टील के केबल थे। बाकी 83 कंटेनर खाली थी। कंटेनर हल्दिया बंदरगाह भेज गए, जहां से खाली कंटेनरों में भी सामान भरकर रूप रवाना किया गया।

बिहार लोक

नदी के तटों पर हरियाली घटी, मछलियों की कई प्रजातियां भी विलुप्त

- जलीय जंतुओं पर प्रदूषित जल का कुप्रभाव, कई मछलियां नदियों में नहीं रहीं
- सोन, पुनपुन और गंगा में जैव विविधता पर प्रतिकूल असर पड़ा
- नदियों पर संकट गहराने से पर्यावरण, स्वास्थ्य पर असर
- प्रदूषित जल में पलीं मछलियां बना रही हैं लोगों को बीमार

पटना, मुख्य संवाददाता। नदियों पर गहराते संकट ने पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य और जलीय जीवों पर व्यापक असर डाला है। जिले की तीन बड़ी नदियां गंगा, सोन और पुनपुन प्रदूषित जल प्रवाहित होने से नदी का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो रहा है। इनके स्वाभाविक प्रवाह में बदलाव से नदी तटों पर हरियाली घटी है। पटना की नदियों से मछलियों की कई प्रजातियां या तो विलुप्त हो गईं या होने के कगार पर हैं। मांगुर, बचवा, बोआरी, गैंची और रीठा जैसी मछलियां कम होती जा रही हैं। प्रदूषित जल प्रवाह से मछलियां, घोंघा, घड़ियाल और डॉल्फिन जैसे जलीय जीवों पर कुप्रभाव पड़ रहा है। विशेषज्ञ बताते हैं कि प्रदूषित जल के संपर्क में आने से मछलियां बीमार हो रही हैं और बाजार में उपलब्धता होने से मानव स्वास्थ्य के लिए संकट बन जा रहा है। खेतों में प्रयुक्त कीटनाशकों और उर्वरकों के भारी मात्रा में प्रयोग से जल विषाक्त हो रहे और नहर और नाले के माध्यम से नदियों में यह घुल रहे हैं। पुनपुन व अन्य नदियों से बाजार में लाई जा रही मछलियों में जिंक व अन्य रसायन अधिक रहने से यह सीधे मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा है।

नदी की धारा पतली, तटों पर पहले की तरह शीतलता नहीं

आर्यभट्ट ज्ञान विवि के नदी अध्ययन केंद्र के समन्वयक डॉ. शाद असगर मोइनी बताते हैं कि पटना जिले की नदियों में विशेषकर पुनपुन में बिना उपचार के अम्लीय व अन्य रासायनिक तत्वों का प्रवाह आसपास के ग्रहण क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है। नदियों के जल का भूगर्भ जल से सीधा रिश्ता है, ऐसे में रसायन घुले नदियों का जल भूजल तक जा रहा है और चापाकल और अन्य माध्यमों से सेवन होने से इससे मानव स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। इधर सोन नदी में कोइलवर के बाद से दो धाराएं बंट गईं। बारिश के दिनों में इस नदी में बाढ़ जैसे हालात होते हैं। साल भर अंधाधुंध खनन ने इस नदी की स्वाभाविक गति को बाधित किया तो इसके तट के आसपास की हरियाली में काफी कमी आई। सोन, पुनपुन और गंगा के तट पर पाये जाने वाले केचुए मर रहे हैं। फरवरी-मार्च आते नदियों का पानी सिमट जा रहा है। पहले जून तक ऐसी स्थिति आती थी। पटना शहर में गंगा के किनारे सैंकड़ों पेड़ पिछले दो दशक में काटे गए या सूख गए। काली घाट, पटना कॉलेज, कलेक्ट्रेट घाट सहित कई घाटों के गंगा के दूर होने से इस इलाके के तापमान पर भी असर पड़ा है। एक समय गर्मियों की दोपहर में गंगा के तट पर शीतलता रहती थी। अब गंगा अपने तटों से काफी दूर चली गई है।

पानी घटने से पटना से मोकामा तक डॉल्फिन पर संकट : सिन्हा

बक्सर से भागलपुर तक गंगा में डॉल्फिन सबसे ज्यादा है। पटना से मोकामा तक डॉल्फिन के लिए संकट की स्थिति है। नदी के पानी का लगातार कम होना और नदी में प्रदूषित पानी का घुलना डॉल्फिन जैसे दुर्लभ जलीय जीवों के लिए हानिकारक है। हालांकि हाल के महीनों में सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट के संचालित होने से गंगा में मलजल के प्रवाह में कमी आई है। पद्मश्री से सम्मानित डॉल्फिन मैन डॉ. आरके सिन्हा बताते हैं कि वर्ष 1993 से 1995 तक के अध्ययन में गंगा में 106 प्रजाति की मछलियां पाई गई थीं। इनमें एक भी विदेशी प्रजाति नहीं थी। फिर 2007 में अध्ययन कराया गया कि 106 प्रजातियां तो मिलीं पर इस बीच आठ-दस प्रजातियां गायब हो गईं और कुछ विदेशी मछलियां गंगा में आ गईं। पिछली बार 2024 में जब इसका अध्ययन कराया गया तो मात्र 76 प्रजातियां मिलीं। अध्ययन में यह भी पता चला कि मछलियों की प्रजाति के साथ साथ इनकी गुणवत्ता और मात्रात्मक स्थिति और वजन में बड़ी कमी आई है। डॉ. सिन्हा बताते हैं कि गंगा में पानी की कमी का बड़ा असर हुआ है। पहले उत्तर बिहार में वेटलैंड्स अधिक थे तो गंगा का पानी ताल तलैया तक जाता था। बारिश के दिनों में एरियर व्यू में पूरा इलाका एकाकार हो जाता था।

Hindustan Page

खुशखबरी. दिसंबर 2025 के सर्वेक्षण में 135 प्रजातियों में से 33 प्रवासी पाये गये

मध्य एशिया से राजगीर आ रहे प्रवासी पक्षी

लाइफ रिपोर्टर @ पटना

राजगीर का वन्य क्षेत्र अब न केवल पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है, बल्कि यूरोप और मध्य एशिया से आने वाले प्रवासी पक्षियों के लिए भी एक सुरक्षित पनाहगाह बन चुका है. वन विभाग द्वारा राजगीर जू सफारी, नेचर सफारी और आसपास के वन्यप्राणी आश्रयणी में किये गये ताजा सर्वेक्षण में पक्षियों की अद्भुत जैव विविधता की पुष्टि हुई है. दिसंबर 2025 में संपन्न दूसरे चरण के इस सर्वेक्षण में कुल 135 पक्षी में 33 प्रजातियां अंतरराष्ट्रीय प्रवासी पक्षियों की हैं. इस उपलब्धि में सबसे महत्वपूर्ण खोज यूरेशियन स्पैरोहॉक रही, जिसे नालंदा जिले में पहली बार देखा गया. इससे स्पष्ट होता है कि राजगीर का परिदृश्य अब वैश्विक प्रवासी पक्षी मार्गों से मजबूती से जुड़ गया है. फरवरी 2025 के पहले चरण में भी 109 प्रजातियां मिली थीं, जिनमें संकटग्रस्त इंडियन वल्चर और ग्रिफॉन वल्चर की मौजूदगी ने पहाड़ियों के पारिस्थितिक महत्व को दर्शाया था.

पक्षियों को मिल रहा आदर्श वातावरण

सर्वेक्षण के दौरान 11 प्रकार की वॉबलर प्रजातियों की पहचान की गयी, जो इस क्षेत्र में स्वस्थ कीट उपलब्धता और कम प्रदूषण का संकेत है. इनमें बूटेड, पैडीफील्ड, और सल्फर-बेलिड वॉबलर जैसे पक्षी शामिल हैं. साथ ही, उत्तरी रूस और साइबेरिया के टुण्ड्रा क्षेत्रों से आने वाला पिन-टेल्ड स्नाइप भी यहां देखा गया. राजगीर जू सफारी के निदेशक राम सुंदर एम के अनुसार, वन विभाग की ओर से किये गये जल और मृदा संरक्षण के कार्यों से जलाशयों में सुधार हुआ है, जिससे पक्षियों को आदर्श वातावरण मिल रहा है. पर्यटकों को बेहतर अनुभव देने के लिए अब सफारी गाइडों को इन पक्षियों की पहचान का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है.

Prabhat khabar Page

प्रभात खबर में पहली बार पढ़िए. कैसे पांच सालों में 95% घट गया गंगा का प्रदूषण

50 साल बाद गंगा नहाने लायक

अनुपम कुमार, पटना

बीते पांच वर्षों में बिहार में गंगा के प्रदूषण में लगभग 95% की कमी आयी है. इससे गंगा अब आधिकारिक रूप से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 50 साल से अधिक समय बाद नहाने लायक हो गयी है. दरअसल, गंगा के पानी को गंदा करनेवाला प्रमुख कारक फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया घटकर 2055 एमपीएन (सबसे संभावित संख्या) प्रति 100 मिलीलीटर पहुंच गया है. वर्ष 1982 में गंगा के पानी में 55,403 फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया पाया गया था. उस समय 1985 में गंगा एक्शन प्लान लाया गया, फिर भी गंगा नहाने लायक नहीं बन पायी. वर्ष 2020-21 में गंगा के पानी में 54 हजार फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया पाया गया था, जो 2021-22 में बढ़कर 66 हजार से भी ज्यादा हो गया था. उसके बाद प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में एसटीपी लगने से इसके मात्रा में तेजी से कमी आनी शुरू हुई. बीते वर्ष तक इसकी मात्रा नौ हजार से अधिक थी, जो नहाने के लिए तय अधिकतम मानक से लगभग चार गुना अधिक थी. लेकिन, छह नये स्थानों पर एसटीपी चालू होने से अब पूरे प्रदेश के गंगा जल का औसत फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया घट कर 2055 पर आ गया है. ऐसे में अधिकतर स्थानों पर गंगा का जल फिर से नहाने लायक हो गया है.

फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया घटकर 2055 एमपीएन

प्रभात नॉलेज

अवधि	फीकल कोलीफॉर्म
2020-21	54812
2021-22	66854
2022-23	56452
2023-24	20860
2024-25	9381
2025-26	2055

नोट : वर्ष 2025-26 के आंकड़े उसके प्रथम छमाही अर्थात अप्रैल 2025 से सितंबर 2025 तक के हैं.

क्या है फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया

पानी के क्वालिटी टेस्ट के लिए उसमें मौजूद आठ तत्वों की जांच होती है. लेकिन पानी की गुणवत्ता को खराब करने और उसे लोगों के पीने नहाने आदि के लिए खतरनाक बनाने में फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की अहम भूमिका होती है. फीकल कोलीफार्म बैक्टीरिया सूक्ष्मजीवों का एक वर्ग है जो जानवरों और मनुष्यों द्वारा उत्सर्जित मल या अपशिष्ट में पाया जाता है.

फीकल कोलीफॉर्म का क्या है मानक

- 00 पीने का पानी
- 500 नहाने का पानी (घरों में सप्लाई मामले में)
- अधिकतम 2500 (खुले स्थानों पर जैसे नदी, तालाब, झील)

● (आंकड़े एमपीएन/100एमएल में)

डाटा एनालिसिस

33 में से 24 प्वाइंट पर नहाने लायक है गंगा का पानी

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद 34 स्थानों पर गंगा जल के गुणवत्ता की जांच के लिए नमूना लेता है. इसमें से 33 स्थानों के अप्रैल 2025 से सितंबर 2025 तक के आंकड़े जारी किये गये हैं. इनमें 24 में फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की संख्या नहाने के लिए तय अधिकतम सीमा 2500 से कम मिली है. खास बात यह है कि शेष नौ स्थानों पर यह 2500 से थोड़ा ही ऊपर है. विशेषज्ञों की मानें तो मार्च तक यहां भी फीकल कोलीफॉर्म के 2500 से नीचे चले जाने की पूरी संभावना है.

कहां-कितना फीकल कोलीफॉर्म : पेज 13

प्रभात इनडेप्थ

एसटीपी की संख्या बढ़ना प्रदूषण घटने की प्रमुख वजह

गंगा के प्रदूषण घटने की प्रमुख वजह गंगा किनारे बसे शहरों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का बनना है. 2020 में प्रदेश में एक भी एसटीपी नहीं था. शहर की नालियों का पानी और मलजल गंगा में सीधे मिल रहा था. इससे उसमें फीकल कोलीफॉर्म बैक्टिरिया की संख्या बढ़ रही थी. अब प्रदेश में 18 एसटीपी हैं और 2027 तक 24 और नये एसटीपी लगाये जायेंगे. इससे गंगा में फीकल कोलीफॉर्म की संख्या को 500 से भी कम के स्तर पर लाने और पानी को और भी स्वच्छ बनाने में मदद मिलेगी.

दानापुर व गुलबी घाट का पानी नहाने लायक

दानापुर व गुलबी घाट का पानी नहाने लायक है. 2500 एमपीएन से थोड़ा ऊपर होने से कुर्जी घाट, गांधी घाट, गायघाट और मालसलामी के पानी को नहाने लायक बनने में दो-तीन महीने का समय लगेगा.

गंगा के प्रदूषण को कम करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें आशातीत सफलता मिली है और अधिकतर स्थानों पर यह नहाने लायक हो गयी है.

डीके शुक्ला, अध्यक्ष, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

Prabhat khabar Page

बिहार में कालाजार उन्मूलन को लेकर तैयार होगा डोसियर

पटना. बिहार में कालाजार उन्मूलन को लेकर डोसियर तैयार किया जा रहा है. इसमें कालाजार से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी शामिल की जायेगी. वर्ष 2022 में राज्य कालाजार उन्मूलन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है. यह स्थिति राज्य को प्रति 10 हजार की आबादी पर एक से कम कालाजार रोगी मिलने के कारण प्राप्त हुई है. अब तीन साल के बाद उसकी वैधता की जांच डब्लूएचओ की टीम द्वारा किया जायेगा. डोजियर में राज्य सरकार द्वारा एक विस्तृत आंकड़ा होगा जिसमें अभी तक कालाजार उन्मूलन के लिए किये गये कार्यों का साक्ष्य पेश किया जायेगा. इसमें दवा का छिड़काव, घर-घर रोगी की खोज, उसका जांच, इलाज, त्वचा के कालाजार रोगियों की पहचान जैसे आंकड़े दर्ज किये जाने हैं. डोजियर में वर्ष 2018 से लेकर 2025 तक किये गये सभी कार्यों का आंकड़ों को दर्ज किया जायेगा. डोजियर तैयार करने को लेकर मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग और पिरामल फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में राजेंद्र स्मारक चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान (आरएमआरआइ) में एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया.

Useful For Mains

वैश्विक ताप से बढ़ती जटिलताएं

दुनिया के ताकतवर देशों को वैश्विक ताप को लेकर कोई चिंता नहीं। आधुनिकीकरण के दौर में लगातार पहाड़ काटे जा रहे हैं। खनन के लिए किए जा रहे विस्फोटों से पहाड़ दरक रहे हैं। मनुष्य की जिंदगी अनिश्चित हो गई है। स्थिति को संभालने के लिए सही दिशा में प्रयास जरूरी हैं।

सुरेश सेठ

वैसे तो कई देशों में प्रदूषण संकट गहरा गया है, लेकिन भारत में इसकी चुनौतियां बेहद गंभीर रूप ले चुकी हैं। पिछले दिनों पर्यावरण और प्रदूषण पर 'लैंसेट' का एक सर्वेक्षण आया। इसके बाद मानसिक रोगियों की देखभाल करने वाली एक संस्था 'इमोनीड्स' का भी एक सर्वेक्षण जारी हुआ। इन दोनों ही सर्वेक्षणों ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। विशेष रूप से भारत के लिए यह चिंता की बात है, जहां विकास के समांतर न तो पर्यावरण को बचाने की फिक्र है और न प्रदूषण को नियंत्रित करने के गंभीर प्रयास दिखते हैं। ये सर्वेक्षण बता रहे हैं कि वायु गुणवत्ता सूचकांक का लगातार 400 से ऊपर रहना, न केवल लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि इसने लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को भी जोखिम में डाल दिया है। अब बच्चे भी खतरे में हैं। वहीं लोगों में स्मृति संबंधी विकार बढ़ा है। इसके अलावा जहरीली हवाओं के लगातार बने रहने से कई बीमारियां पैदा हो रही हैं।

सर्वेक्षण बता रहे हैं कि प्रदूषण से न केवल सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बल्कि हृदय और एलर्जी संबंधी समस्याएं भी लोगों को हो रही हैं। अल्जाइमर और पार्किंसन की चपेट में भी लोग आ रहे हैं। सर्वेक्षण में भारतीयों की मुश्किलों का भी जिक्र है। कहा गया है कि इस प्रदूषण ने लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता घटा दी है और अब हालत ऐसी हो गई है कि एंटीबायोटिक दवाइयां भी कम असर कर रही हैं। देश में निरंतर बढ़ते प्रदूषण के कारण ऋतु चक्र में असाधारण बदलाव आया है। बढ़ते वैश्विक ताप की वजह से जटिलताएं बढ़ रही हैं। बर्फ गिरने की प्रकृति बदल रही है। हिमनद हमारे जलस्रोत हैं। ये नदियों को पानी और बादलों को घुमड़न देते हैं। खेतों में फसलों को जीवन भी मिलता है। मगर अब बर्फ कम पड़ रही है और जो हिमनद बनते हैं, वे जल्दी पिघलने लगते हैं। इसी कारण बाढ़ के खतरे बढ़ गए हैं और लोगों का जीवन अनिश्चित हो गया है। जलवायु संकट की यह भयावह तस्वीर है।

ऐसी में सभी का दायित्व है कि वह प्रदूषण को किसी भी तरह नियंत्रित करने के लिए हरसंभव योगदान दें। सरकारें कदम उठाएं। वैश्विक ताप पर नियंत्रण के लिए ठोस उपाय हों। नारों और भाषणों से कुछ भी हासिल नहीं होगा। प्रदूषण से दुनिया के ज्यादातर देश बेहाल हैं। गरीब देशों के सामने संकट है, लेकिन समर्थ देश इस लड़ाई में अपना योगदान देने के लिए तैयार नहीं हैं। उनका विचित्र तर्क है कि कार्बन उत्सर्जन तो तीसरी दुनिया के वे देश कर रहे हैं जो अब विश्व में चौथी औद्योगिक क्रांति का अगुआ बनना चाहते हैं। वैश्विक ताप को लेकर ताकतवर देशों को कोई चिंता नहीं। आधुनिकीकरण के दौर में लगातार पहाड़ काटे जा रहे हैं। खनन के लिए किए जा रहे विस्फोटों से धरती कांप रही है। कई पहाड़ दरक रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में स्थिति गंभीर है। मनुष्यों की जिंदगी अनिश्चित हो गई है। लिहाजा अब सचेत होने का समय है।

मौसम का चरित्र बदल रहा है। बरसात के मौसम में बारिश नहीं होती और जब मानसून की विदाई का समय आता है, तो बादल फटने लगते हैं। पिछले वर्ष हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से लेकर मंडी जिले तक बार-बार जल प्रलय हुआ। इन घटनाओं ने खतरे की घंटी बजा दी है। प्रकृति ने मनुष्यों को सचेत होने का संदेश दे दिया है। उत्तराखंड में धरती कांपती है, भूकम्प आते हैं और गांवों के गांव नक्शे से गायब हो जाते हैं। मगर लोगों को कोई यह नहीं समझाता कि जीवन जीने का सहज तरीका ही सर्वोत्तम है। ऐसा लगता है कि विकास की दौड़ में हम प्रकृति का ही विध्वंस करेंगे। ऐसे में जरूरी है कि अब वैज्ञानिकों की बताई सावधानियां बरती जाएं।

> प्रदूषण से न केवल सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बल्कि हृदय और एलर्जी संबंधी समस्याएं भी हो रही हैं। अल्जाइमर और पार्किंसन की चपेट में भी लोग आ रहे हैं। पिछले दिनों आए एक सर्वेक्षण में भारतीयों की मुश्किलों का भी जिक्र है। कहा गया है कि प्रदूषण ने लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता घटा दी है और अब हालत ऐसी हो गई है कि एंटीबायोटिक भी कम असर कर रही हैं। देश में निरंतर बढ़ते प्रदूषण के कारण ऋतु चक्र में असाधारण बदलाव आया है। बढ़ते वैश्विक ताप की वजह से जटिलताएं बढ़ रही हैं। बर्फ गिरने की प्रकृति बदल रही है, जबकि हिमनद हमारे जलस्रोत हैं।

इसी संदर्भ में अरावली पहाड़ियों का मुद्दा एक महत्त्वपूर्ण संदर्भ के रूप में सामने है। खनन माफिया की यही कोशिश रही है कि अरावली पर्वतमाला से अपने खनन व्यापार का हित साधा जाए। अरावली की जो छोटी पहाड़ियां हैं, वहां खनन किसी से छिपा नहीं है। इस समय यह पर्वत शृंखला संकट के दौर से गुजर रही है। पहाड़ी क्षेत्र में किस तरह संकट पैदा होते हैं, इसका सामना उत्तराखंड और हिमाचल ने बार-बार किया है। अरावली शृंखला दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक फैली है। यहां खनन पट्टों के आबंटन पर रोक लगे, ऐसी मांग लोग करते रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी आवाज उठाई। गौरतलब है कि अरावली की पहाड़ियां थार रेगिस्तान और उत्तरी मैदानों के बीच एक दीवार का काम करती हैं। इनमें कई पहाड़ियों की ऊंचाई कम है। पहले यह आदेश हुआ कि एक पर्वत शृंखला से दूसरी शृंखला तक 500 मीटर से अधिक का अंतर हो या सौ मीटर से अधिक की ऊंचाई हो, तो ऐसे पहाड़ी समूहों पर खनन प्रतिबंध लग जाएगा। बाकी क्षेत्रों पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया जाए। मगर फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही इस निर्णय पर पुनर्विचार किया और खनन पट्टों पर न केवल रोक लगाई, बल्कि अपने पिछले निर्णय पर भी रोक लगा दी।

कोई दो राय नहीं कि अरावली पर्वत शृंखला को किसी भी हाल में संरक्षित करना होगा। इस मुद्दे पर अब शीर्ष न्यायालय भी सख्त है, लेकिन हमें अब अन्य पर्वत शृंखलाओं पर भी ध्यान देना होगा। उन्हें बचाना होगा। अंधाधुंध विकास मानव जाति के लिए तबाही ही लाएगा, नहीं तो विकास की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। समस्या केवल पहाड़ों की नहीं है या उन मैदानी क्षेत्रों की नहीं है, जहां भूकम्प की लगातार आशंका बनी रहती है। यों दिल्ली से लेकर पंजाब और हिमाचल तक कई इलाकों में भूकम्प की आशंका बनी रहती है। इसलिए यहां जो भी विकास होता है, वह इस तरह होना चाहिए कि भूकम्प से बचाव हो सके।

दूसरी ओर प्रदूषण का असली कारण क्या है, इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। पहले तो पंजाब पर आरोप लगता रहा कि वहां पराली जलाने से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है और वायु गुणवत्ता सूचकांक चार सौ से ऊपर पहुंच जाता है, लेकिन अब विशेषज्ञों ने स्पष्ट कर दिया है कि यह तो अंधाधुंध विकास का नतीजा है। वाहनों की बढ़ती समस्या भी चिंता का विषय है। कचरे का उचित ढंग से निस्तारण न हो पाना भी एक चुनौती है। पराली न जलाने के लिए अभियान तो चलाया गया है, लेकिन प्रदूषण का समाधान कैसे होगा? स्वाभाविक है कि इसके लिए एक दीर्घकालिक ठोस नीति बनानी पड़ेगी। पराली पर राजनीति करने या नारेबाजी से समस्या नहीं सुलझेगी। पंजाब में तो नेतृत्व बार-बार कहता है कि हमने तो इस पर लगाम लगा दी, लेकिन क्या अन्य पड़ोसी राज्यों में पराली नहीं जलती, वाहनों से प्रदूषण क्या नहीं फैलता और क्या कूड़े का उचित निस्तारण हो जाता है? जवाब है, नहीं। सवाल यह भी है कि राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश तक जानलेवा घुटन क्यों है? स्पष्ट है कि हमें समस्या की तह में जाना होगा।

Jansatta Page. No-6

मंथन

प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ पत्रकार

संयुक्त राष्ट्र की लाचारी

वेनेजुएला के परिप्रेक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र को कुछ ऐसा करना होगा, जिससे इसकी वैश्विक प्रतिष्ठा के प्रति सदस्य देशों का विश्वास पुनः स्थापित हो सके

वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई के मामले पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हुई बैठक। संयुक्त राष्ट्र

हाल में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस की अमेरिका द्वारा की गई गिरफ्तारी मामले पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की आपात बैठक हुई। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस इस घटनाक्रम पर गहरी चिंता जताने के अलावा अमेरिका के विरुद्ध कोई भी कड़ी कार्रवाई करने के परिप्रेक्ष्य में लाचार नजर आए। जबकि संयुक्त राष्ट्र चार्टर साफ कहता है कि किसी भी देश की क्षेत्रीय अखंडता एवं राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध बल का प्रयोग नहीं किया जा सकता।

दुनिया के तेल भंडार का 18.17 प्रतिशत अर्थात लगभग 303 अरब बैरल तेल और दुर्लभ खनिजों के भंडार वेनेजुएला की धरती में समाए हुए हैं। किंतु उसके पास कच्चे तेल को शोधन करने के तकनीकी संसाधन नहीं हैं, इसलिए वह इस तेल को ईंधन में नहीं बदल पा रहा है। इस तेल के शोधन के लिए जब मादुरो ने चीन से तेल और रूस से हथियार खरीदने की नीति को अंजाम दिया तो ट्रंप की नाराजगी बढ़ गई और मादुरो तथा उनकी पत्नी सिलिया को गिरफ्तार करवा लिया। हालांकि अमेरिका ने वेनेजुएला पर अमेरिका में मादक पदार्थों की तस्करी करने का आरोप लगाकर इस सैन्य कार्रवाई को जायज ठहराया है। मादुरो को अमेरिकी कानून केस-फ्रिस्बी के तहत पकड़ा गया है। यह कानून अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद-2 के तहत राष्ट्रपति को ऐसे लोगों और भगोड़ों को पकड़ने की अनुमति देता है, जो अमेरिका को किसी प्रकार से नुकसान पहुंचा रहे हों। इसमें प्रविधान है कि गिरफ्तारी का तरीका कितना भी गैरकानूनी हो, एक बार अमेरिका में लाने के बाद अमेरिकी अदालत में मामला चलाया जा सकता है और इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। मादुरो पर मादक पदार्थ तस्करी के आपराधिक मामले अमेरिका में दर्ज हैं, जिनमें कम से कम 20 साल की सजा से लेकर आजीवन कारावास तक का प्रविधान है।

अमेरिका कभी मादक पदार्थों और कभी हथियारों की तस्करी का बहाना ढूंढकर अपने शत्रु राष्ट्रों के मुखियाओं को सबक सिखाता रहा है। 2003 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जार्ज डब्ल्यू बुश की सरकार ने इराक पर जैविक और रासायनिक हथियार होने का दावा कर उसे नेस्तनाबूद कर दिया था। इसी तरह 2011 में अमेरिका और नाटो ने लीबिया और सीरिया में भी सैन्य हस्तक्षेप कर वहां की वर्तमान सरकारों को अपदस्थ कर दिया था। अमेरिका के सरकारी शोध संस्थान कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस की रिपोर्ट के अनुसार, अब तक अमेरिका दुनिया में 469 सैन्य हस्तक्षेप कर चुका है, जिससे उसे महाशक्ति माना जाता रहा है।

दूसरे विश्व युद्ध के बाद शांतिप्रिय देशों के संगठन के रूप में संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ था। इसका अहम उद्देश्य भविष्य की पीढ़ियों को युद्ध की विभीषिका और आतंकवाद से सुरक्षित रखना है। भारत का तीन बार पाकिस्तान और एक बार चीन से युद्ध हो चुका है। इराक और अफगानिस्तान, अमेरिका और रूस के जबरन हस्तक्षेप के कारण ऐसी युद्ध-विभीषिका के शिकार हुए कि आज तक उबर नहीं पाए हैं। रूस-यूक्रेन तथा इजरायल-हमास के बीच युद्ध एक न टूटने वाली कड़ी बन गया है। अनेक इस्लामिक देश गृह-कलह से जूझ रहे हैं। उत्तर कोरिया और पाकिस्तान बेखौफ परमाणु युद्ध की धमकी देते रहते हैं। दुनिया में फैले इस्लामिक आतंकवाद पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। साम्राज्यवादी नीतियों के क्रियान्वयन में लगा चीन किसी वैश्विक पंचायत के आदेश को मानने को तैयार नहीं है।

संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, यूनिसेफ और शांति सेना जैसे संगठन कार्यरत हैं, किंतु चंद देशों की शक्ति के आगे ये संगठन नतमस्तक दिखाई देते हैं। यही कारण है कि शांति सेना की बढ़ते सैनिक संघर्षों के बीच कोई निर्णायक भूमिका नजर नहीं आती। अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों द्वारा आर्थिक सहायता में कटौती किए जाने से इन संगठनों का भविष्य भी संकट में है। इन सभी परिस्थितियों के चलते इस वैश्विक मंच की विश्वसनीयता पर संकट गहराता जा रहा है। अतः इसमें पर्याप्त और तत्काल सुधार आवश्यक हैं। वेनेजुएला के परिप्रेक्ष्य में भी संयुक्त राष्ट्र को कुछ ऐसा करना होगा, जिससे इसकी वैश्विक प्रतिष्ठा के प्रति सदस्य देशों का विश्वास पुनः स्थापित हो सके।

दुनिया में लगातार ऐसे हालात बनने के बावजूद संयुक्त राष्ट्र की कार्य-संस्कृति लाचार बनी हुई है। उस पर निरंतर प्रश्नचिह्न उठ रहे हैं। अतः यदि यह वैश्विक संस्था अपने भीतर समयानुकूल सुधार नहीं लाती तो कालांतर में महत्वहीन होती चली जाएगी। फिर इसके सदस्य देशों को इसकी आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी।

Dainik Jagaran Page No-9

असहमति का भी सम्मान होना चाहिए

मनोज कुमार झा | सदस्य, राज्यसभा

जो शब्द कभी देशद्रोह या हिंसक षड्यंत्र जैसे गंभीर आरोपों के लिए सुरक्षित था, वह अब असहमति जताने वाले विपक्ष या नागरिकों के लिए सहज राजनीतिक हथियार बन गया है।

दुनिया भर में लोकतंत्र अपने स्वभाव से ही प्रतिस्पर्द्धी व्यवस्था है। विभिन्न राजनीतिक दल, परस्पर टकराती विचारधाराएं और जनहित व लोकोन्मुख राजनीति की भिन्न व्याख्याएं- ये लोकतंत्र की कमजोरी नहीं, उसकी ताकत हैं। एक परिपक्व लोकतंत्र में राजनीतिक विपक्ष बाधा नहीं, बल्कि संतुलन का माध्यम होता है। इस अर्थ में प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दल लोकतंत्र के आभूषण हैं, जो उसे सौंदर्य, गहराई व मजबूती प्रदान करते हैं। जब विपक्ष को बार-बार 'राष्ट्र-विरोधी' कहा जाने लगे, तब लोकतंत्र की यह आभा फीकी पड़ने लगती है। उससे भय और संदेह का वातावरण बनता है।

भारतीय लोकतंत्र कभी भी शांत या एकस्वर नहीं रहा। समरूप सोच को भारतीय लोकतंत्र ने कभी नैसर्गिक गहना नहीं समझा। संविधान सभा की बहसों से लेकर आज के संसदीय टकरावों तक, असहमति इसकी स्थायी विशेषता रही है। संविधान निर्माताओं ने भारत की सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए जान-बूझकर सर्वसम्मति के मिथक को खारिज किया। उन्होंने ऐसे गणराज्य की कल्पना की थी, जहां सरकार की आलोचना को राष्ट्र से शत्रुता नहीं समझा जाएगा, और असहमति को देशभक्ति के विरुद्ध अपराध नहीं माना जाएगा। आज यह बुनियादी फर्क धुंधला-सा होता दिख रहा है।

राजनीतिक विरोधियों को 'राष्ट्र-विरोधी' ठहराने की बढ़ती प्रवृत्ति लोकतांत्रिक संस्कृति में एक खतरनाक बदलाव का संकेत है। जो शब्द कभी देशद्रोह या हिंसक षड्यंत्र जैसे गंभीर आरोपों के लिए सुरक्षित था, वह अब असहमति जताने वाले नागरिकों, आंदोलनकारियों, पत्रकारों और विपक्षी दलों के लिए सहज राजनीतिक हथियार बन गया है। यह केवल भाषा में अतिवाद का लक्षण मात्र नहीं है, बल्कि यह सायास रणनीति लगने लगी है। जब विरोधी को राष्ट्र-विरोधी घोषित कर दिया जाता है, तब उसके तर्कों से संवाद करने की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है।

इस तरह की प्रवृत्तियां गहरे स्तर पर लोकतंत्र को प्रभावित करती हैं। राष्ट्र किसी भी सरकार से बड़ा और किसी भी राजनीतिक दल से पुराना होता है और निरंतरता में होता है। जब राष्ट्रभक्ति को किसी एक राजनीतिक दल की कथा से जोड़ दिया जाता है, तब लोकतंत्र नैतिक कट्टरता की ओर फिसलने लगता है। राजनीति विचारों की प्रतिस्पर्द्धा न रहकर 'देशभक्त' और 'देशद्रोही' के बीच नैतिक युद्ध में बदल जाती है।

भारतीय इतिहास इस सोच का स्पष्ट प्रतिवाद प्रस्तुत करता है। हमारा स्वतंत्रता संग्राम स्वयं गहरे मतभेदों से भरा था- चाहे वे मतभेद संघर्ष के तरीकों को लेकर हों, सामाजिक न्याय की परिभाषा को लेकर हों या भविष्य के भारत की संरचना को लेकर। गांधी और आंबेडकर के बीच जाति और सामाजिक सुधार पर तीखे मतभेद थे; नेहरू और पटेल के आर्थिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण अलग-अलग थे; समाजवादी, उदारवादी और क्रांतिकारी एक-दूसरे से असहमत थे। इन मतभेदों को कभी राष्ट्र के प्रति विश्वासघात नहीं कहा गया। एक साझा राष्ट्रीय उद्देश्य की स्वीकृति ने असहमति को विनाशकारी बनने से रोके रखा।

यही नैतिक आत्मविश्वास स्वतंत्र भारत के शुरुआती वर्षों में भी दिखाई देता है। विपक्ष सरकार का तीखा आलोचक था, पर उसकी देशभक्ति पर प्रश्नचिह्न नहीं लगाया जाता था। संसद में बहसें तीखी होती थीं, लेकिन उनकी भाषा सांविधानिक मर्यादा में रहती थी। असहमति और राष्ट्रप्रेम के सह-अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए किसी विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं थी, यह लोकतांत्रिक समझ का हिस्सा था।

जब राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी शत्रु में बदल दिए जाते हैं, तब संस्थाएं कमजोर होने लगती हैं। संसद विचार-विमर्श के मंच के बजाय नारेबाजी का रंगमंच बन जाती है। इससे भी अधिक खतरनाक यह है कि नागरिकों को यह सिखाया जाने लगता है कि सत्ता से प्रश्न करना राष्ट्र के खिलाफ खड़ा होना है। भयग्रस्त लोकतंत्र कभी मजबूत नहीं होता। वह विविधता से शक्ति लेने के बजाय एकरूपता में सुरक्षा खोजता है।

यह प्रवृत्ति राष्ट्रवाद को भी खोखला कर देती है। जब देशभक्ति एक राजनीतिक हथियार बन जाती है, तब उसका नैतिक अर्थ नष्ट हो जाता है। सच्चा राष्ट्रप्रेम देश की उपलब्धियों पर गर्व के साथ-साथ उसकी कमियों को स्वीकार करने और अन्याय को चुनौती देने का साहस भी मांगता है। आलोचना से डरने वाला राष्ट्रवाद आत्मविश्वासी नहीं, असुरक्षित होता है। वह मौन को एकता और आज्ञापालन को निष्ठा समझने लगता है।

संविधान सभा की बहसें और उससे निर्मित संविधान इस संदर्भ में हमारा सबसे स्पष्ट मार्गदर्शक है। वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, असहमति के अधिकार और राजनीतिक विपक्ष की वैधता को सुनिश्चित करता है। वह एकमतता की मांग नहीं करता, बल्कि सांविधानिक निष्ठा की अपेक्षा करता है। यह निष्ठा सत्ता में बैठे लोगों के प्रति अंध-समर्थन में नहीं, बल्कि न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व जैसे मूल्यों की रक्षा में निहित है। आज की सबसे बड़ी चिंता यह है कि विरोधियों को अवैध ठहराने की भाषा सामान्य होती जा रही है।

इसलिए यह संकट केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि नैतिक और मानसिक भी है। जो लोकतंत्र असहमति को शत्रुता में बदले बिना संभाल नहीं सकता, वह एक तरह की सामूहिक मानसिक बीमारी से ग्रस्त हो जाता है। वह भिन्नता के साथ जीने की परिपक्वता खो देता है। इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए सभी पक्षों में संयम आवश्यक है। राजनीतिक नेतृत्व को आसान अपमानजनक भाषा से बचना होगा, और नागरिकों को असहमति तथा राष्ट्र-विरोध के बीच फर्क समझना होगा। लोकतांत्रिक नैतिकता की पुनःस्थापना आवश्यक है- जहां विरोधियों की आलोचना हो, पर उनका अमानवीकरण न किया जाए।

भारत आज एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है, जहां से दो रास्ते निकलते हैं- एक रास्ता उस गणराज्य की ओर जाता है, जो असहमति को आत्मविश्वास के साथ स्वीकार करता है, और दूसरा उस लोकतंत्र की ओर, जो संदेह और बहिष्कार से खुद को खोखला कर लेता है। इतिहास का मत इस संदर्भ में बिल्कुल स्पष्ट है। राष्ट्र प्रभुत्व से नहीं, बल्कि नैतिक संयम से टिकते हैं; एकरूपता से नहीं, बल्कि न्याय से मजबूत होते हैं; और मतभेदों को दबाकर नहीं, बल्कि उन्हें लोकतांत्रिक ढंग से समाहित करके आगे बढ़ते हैं। यदि भारत को अपने लोकतंत्र की चमक बनाए रखनी है, तो उसे राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को राष्ट्र का शत्रु नहीं, बल्कि साझा राष्ट्रीय यात्रा के अनिवार्य सहभागी के रूप में देखना होगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

Hindustan Page-14

कुपोषण से लड़ाई ▶ सीएसआर कान्क्लेव में गोयल ने कुपोषण मुक्त भारत के लिए सामूहिक प्रयास पर दिया जोर

सीएसआर को दो प्रतिशत की सीमा में नहीं बांधें

कहा, स्वस्थ्य बच्चे ही भविष्य में अच्छे कर्मचारी, अच्छे नागरिक और जिम्मेदार उपभोक्ता बनेंगे

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कारपोरेट कंपनियों को सलाह दी है कि सामाजिक जिम्मेदारी यानी सीएसआर को केवल कानून की बाध्यता न मानें और इसे दो प्रतिशत की सीमा में न बांधें। उन्होंने कहा कि कानून में तय दो प्रतिशत को न्यूनतम स्तर समझना चाहिए न कि अधिकतम। कुपोषण की समस्या को समाप्त करने के लिए उन्होंने सरकार के साथ ही कारपोरेट जगत, समाज और आम लोगों से भी आगे आने की अपील की। राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) द्वारा मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित पोषण पर राष्ट्रीय सीएसआर कान्क्लेव को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कुपोषण के विरुद्ध लड़ाई को आंदोलन बनाना होगा। जब तक हर स्तर पर सामूहिक प्रयास नहीं होंगे, तब तक देश को कुपोषण मुक्त बनाना मुश्किल है। 2047 तक विकसित भारत का सपना तभी पूरा हो सकता है, जब देश का हर बच्चा स्वस्थ होगा।

नई दिल्ली में मंगलवार को आयोजित पोषण सुरक्षा एवं कुपोषण निर्मूलन अभियान में कारपोरेट कंपनियों की सामाजिक जिम्मेदारी की भूमिका विषयक राष्ट्रीय कान्क्लेव के दौरान बच्चों से बात करते केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। एएनआइ

गोयल ने कहा कि सीएसआर कोई बोझ नहीं है, बल्कि समाज के लिए कुछ करने का अवसर है। खासकर कुपोषण जैसी समस्या में सीएसआर की भूमिका बेहद अहम है। उन्होंने समझाया कि पोषण पर खर्च करना दरअसल देश के भविष्य में निवेश करना है। स्वस्थ बच्चे ही भविष्य में अच्छे कर्मचारी, अच्छे नागरिक और जिम्मेदार उपभोक्ता बनेंगे। इससे कंपनियों और देश दोनों को लाभ होगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारत जिस तेजी से करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का प्रयास कर रहा है, उसी संकल्प के साथ कुपोषण को खत्म करने की जरूरत है। लक्ष्य होना चाहिए कि देश में कोई भी बच्चा कुपोषित न रहे और रोकी जा सकने वाली बीमारियों के साथ जन्म न ले।

उन्होंने कंपनियों से आग्रह किया कि उनकी सामाजिक गतिविधियां केवल शहरों तक सीमित न रहें, बल्कि गांवों और दूर-दराज के इलाकों तक पहुंचें। गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों के पोषण पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कुपोषण की शुरुआत अक्सर जन्म से पहले ही हो जाती है। कार्यक्रम में दो नई सीएसआर पहल भी शुरू की गईं। भिलाई स्टील प्लांट का 'गिफ्टमिल्क कार्यक्रम' छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले करीब चार हजार बच्चों को विटामिन ए और डी से युक्त दूध उपलब्ध कराएगा। वहीं, आइडीबीआइ बैंक का 'शिशु संजीवनी कार्यक्रम' महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में आंगनबाड़ी केंद्रों के लगभग तीन हजार बच्चों को पौष्टिक आहार देगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेरी मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने कहा कि बचपन और गर्भावस्था के दौरान सही पोषण ही कुपोषण से निपटने का सबसे असरदार तरीका है। उन्होंने बताया कि दूध और दुग्ध उत्पाद बच्चों की प्रोटीन की जरूरत का बड़ा हिस्सा पूरा कर सकते हैं।

Dainik Jagaran Page No-3

सामाजिक सुरक्षा के विस्तार से सशक्त होगा समाज

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुआई में राजग सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों और सामाजिक सुरक्षा पर जोर दिए जाने से पिछले दस वर्ष में 25 करोड़ से अधिक लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। एक बड़ी आबादी का जीवन स्तर बेहतर हुआ है। इसमें डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (डीबीटी) जैसी पहलों का अहम योगदान रहा है। डीबीटी के तहत पिछले नौ वर्षों के दौरान करीब 28 लाख करोड़ रुपये लाभार्थियों तक पहुंचाए गए हैं। उम्मीद है कि केंद्र सरकार 2026 में सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करेगी।

2.3%
था 2022-23 में रोज 2.15 डालर से कम पर जीवन यापन करने वाले लोगों का अनुपात

16.2%
था 2011-12 में इस अवस्था में जीवन यापन करने वाले लोगों का अनुपात

ग्रामीण और शहरी गरीबी में कमी

विश्व बैंक की रिपोर्ट में पाया गया है कि अत्यधिक गरीबी में आई तीव्र कमी व्यापक स्तर पर हुई है, जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र शामिल हैं। यह उपलब्धि भारत सरकार की समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

2.8%
हो गई है 2022-23 में ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक गरीबी, 2011-12 में 18.4 प्रतिशत से घटकर

10.7%
से घटकर 1.1 प्रतिशत हो गई शहरी केंद्रों में इसी अवधि में अत्यधिक गरीबी

1.7%
हो गया ग्रामीण और शहरी गरीबी के बीच का अंतर 7.7 प्रतिशत अंक से घटकर

निम्न-मध्यम आय वालों की स्थिति

भारत ने निम्न-मध्यम आय स्तर (प्रति दिन 3.65 डालर) पर गरीबी कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में इस व्यापक प्रगति से लाखों लोगों को लाभ हुआ है।

28.1%
रह गई है 2022-23 में प्रति दिन 3.65 डालर की गरीबी रेखा पर भारत की गरीबी दर

69.1%
से घटकर 32.5 प्रतिशत हो गई इस अवधि में ग्रामीण गरीबी

7.01%
की गिरावट के साथ 25 से घटकर 15% रह गया ग्रामीण-शहरी गरीबी का अंतर

गरीबी कम करने में योगदान देने वाले राज्य

उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल व मध्य प्रदेश, 2011-12 में भारत के 65 प्रतिशत अत्यधिक गरीब लोगों का प्रतिनिधित्व करते थे। 2022-23 तक, इन राज्यों ने अत्यधिक गरीबी में समग्र गिरावट में दो-तिहाई योगदान दिया।

रोजगार वृद्धि

देश में 2021-22 के बाद से रोजगार वृद्धि में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सुधार हुआ है। 2021-22 से रोजगार वृद्धि कामकाजी उम्र की आबादी से अधिक रही है। वित्त वर्ष 2024-25 में शहरी बेरोजगारी घटकर 6.6 प्रतिशत हो गई जो 2017-18 के बाद सबसे कम है।